Vishv UMIYA Foundation | VUF INSTITUTE CIVIL SERVICES

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 03-07-25

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Thursday, 03 July, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 2 : International Relations**	ब्रिक्स संतुलित 'बहुध्रुवीय' विश्व व्यवस्था बनाएगा: प्रधानमंत्री
Page 06 **Syllabus : GS 2 : Social Justice**	''कोविड-19 टीकों और अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई संबंध नहीं''
Page 06 **Syllabus : GS 3 : Science and Technology**	आईएसएस की एक्सिओम-4 यात्रा गगनयान मिशन के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगी: इसरो
Page 07 **Syllabus : GS 3 : Science and Technology**	सिंहली लोग दक्षिण भारत से पलायन कर आदिवासियों के साथ मिल गए: अध्ययन
Page 09 **Syllabus : GS 3 : Indian Economy**	क्या गिग वर्कर भारत के श्रम डेटा का हिस्सा हैं?
Page 08 : Editorial Analysis: **Syllabus : GS 2 : International Relations**	वैश्विक विकास वित्त को फिर से परिभाषित करना

Page 01 : GS 2 : International Relations

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पांच देशों की यात्रा - जिसमें घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, नामीबिया और ब्राजील (ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए) शामिल हैं - का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करना, रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना है।

BRICS will create a balanced 'multipolar' world order: PM

PM lands in Ghana as he begins his five-nation trip; he says the visits will strengthen cooperation within Global South; Modi will also attend the BRICS summit in Brazil and hold meetings; he will receive state honours of Ghana, Trinidad and Tobago

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

India and Brazil will discuss ways to advance the priorities of the Global South in the coming days, said Prime Minister Narendra Modi ahead of his five-nation visit beginning on Wednesday.

Mr. Modi, who will attend the BRICS summit to be held in Brazil's Rio De Janeiro during the trip, said the summit will help create a "balanced multipolar world order". He further said the five-nation visit will help strengthen cooperation within the Global South. The Prime Minister is expected to hold several bilateral meetings on the sidelines of the summit as well.

Pleasant ties: Prime Minister Narendra Modi being welcomed by Ghana President John Mahama in Accra on Wednesday. ANI

Argentina on itinerary

"As a founding member, India is committed to BRICS as a vital platform for cooperation among emerging economies. Together, we strive for a more peaceful, equitable, just, democratic and balanced multipolar world order," said Mr. Modi in a departure statement as he boarded the official aircraft that landed in Ghana for a bilateral visit.

The Prime Minister will also visit Trinidad and Tobago, Argentina, and Namibia, before concluding the trip on July 9.

According to Ghanaian news outlet *Graphic.com.gh*, the Foreign Minister of Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa had announced that Mr. Modi will receive the country's highest state honour, the Companion of the Order of the Star of Ghana, during the visit. Previous recipients of the honour include the late French President Jacques Chirac, King Mohammed VI of Morocco, President Luiz Inácio 'Lula' da Silva of Brazil, former Nigerian President Olusegun Obasanjo, and former Namibian President Sam Nujoma.

Mr. Modi will hold talks with President John Dramani Mahama in Ghana. "Ghana is a valued partner in the Global South and plays an important role in the African Union and the Economic Community of West African States (ECOWAS)," said Mr. Modi, adding that his visit will build on India's historic ties with Ghana and help in opening up areas like investment, energy, health, capacity building and development partnership.

Mr. Modi will also address the Parliament of Ghana during the visit. Mr. Ablakwa has said that Ghana plans to emerge as the "vaccine hub" for Africa and talks would be held with Mr. Modi during the visit regarding vaccine production in Ghana.

From Ghana, Mr. Modi will fly to Trinidad and Tobago where he will be hosted by Prime Minister Kamla Persad Bissessar.

"This visit will provide an opportunity to rejuvenate the special bonds of ancestry and kinship that unite us," said Mr. Modi. The Government of Trinidad and Tobago has announced that Mr. Modi will be conferred with the Order of the Republic of Trinidad and Tobago, the highest state honour of the Caribbean nation.

Following the BRICS summit, Mr. Modi will proceed to Brasilia for a state visit.

On the way back home, Mr. Modi will stop at Namibia. Mr. Modi will meet President Netumbo Nandi Ndaitwah and address the Joint Session of Namibian Parliament.

संदर्भ और महत्व

- वैश्विक दक्षिण फोकस: भारत वैश्विक दक्षिण के लिए वकालत करता रहा है - वैश्विक शासन में विकासशील और कम प्रतिनिधित्व वाले राष्ट्र। यह यात्रा इस ब्लॉक में भारत की नेतृत्व आकांक्षाओं को पुष्ट करती है।

- ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक रणनीतिक गठबंधन के रूप में उभर रहा है जो आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी पश्चिमी-प्रभुत्व वाली संस्थाओं के विकल्प की तलाश कर रहा है।
- बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था: प्रधानमंत्री मोदी का "संतुलित बहुध्रुवीय विश्व" पर जोर एकध्रुवीय/आधिपत्यवादी प्रभुत्व को चुनौती देता है और समानता, लोकतंत्र और शांति में निहित एक न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की तलाश करता है।
- द्विपक्षीय सुदृढ़ीकरण: इस यात्रा में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता शामिल है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और भू-राजनीतिक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

मुख्य आकर्षण

- **ब्रिक्स और भारत की रणनीतिक भूमिका**
  - o भारत ब्रिक्स को "उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच" के रूप में देखता है।
  - o शिखर सम्मेलन वित्त, डिजिटल अवसंरचना, वैश्विक शासन सुधार और दक्षिण-दक्षिण सहयोग में सहयोग को मजबूत कर सकता है।
  - o संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार, समान वैश्विक निर्णय लेने और डी-डॉलरीकरण पहलों के लिए आह्वान को मजबूत करता है।
- **भारत-अफ्रीका संबंध (घाना और नामीबिया)**
  - o घाना अखिल अफ्रीकी आउटरीच के लिए रणनीतिक रूप से AU और ECOWAS का सदस्य है।
  - o वैक्सीन उत्पादन, ऊर्जा, क्षमता निर्माण और निवेश पर बातचीत भारत के अफ्रीका-केंद्रित विकास मॉडल का हिस्सा है।
  - o नामीबिया में, प्रधानमंत्री राजनीतिक सद्भावना और ऐतिहासिक संबंधों (जैसे, उपनिवेश-विरोधी संघर्ष के दौरान SWAPO को भारत का समर्थन) को बढ़ावा देने के लिए इसकी संसद को संबोधित करेंगे।
- **भारत-लैटिन अमेरिका और कैरिबियन संबंध (अर्जेंटीना और त्रिनिदाद और टोबैगो)**
  - o त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ सांस्कृतिक और प्रवासी संबंध; पीएम को सर्वोच्च राज्य सम्मान मिलेगा।
  - o भारत का लक्ष्य G20 सदस्य और प्रमुख कृषि शक्ति अर्जेंटीना में व्यापार और कूटनीतिक पहुंच का विस्तार करना है।
  - o यह क्षेत्र भारत के व्यापार भागीदारों और खाद्य-ऊर्जा सुरक्षा के विविधीकरण के लिए आवश्यक है।

भारत के लिए रणनीतिक निहितार्थ

1. वैश्विक दक्षिण में नेतृत्व

- o विकासशील देशों के लिए एक विश्वसनीय आवाज़ के रूप में भारत की स्थिति।
- o स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और शिक्षा सहयोग के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर और विकासात्मक कूटनीति को बढ़ाता है।

2. बहुध्रुवीयता और रणनीतिक स्वायत्तता

- o एक ऐसी विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देता है जो पश्चिम-केंद्रित नहीं है।
- o सुधारित बहुपक्षवाद, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक और मुद्रा सहयोग के लिए भारत के प्रयास को मजबूत करता है।

3. भू-राजनीतिक पहुंच

- o भारत की अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की भागीदारी को मजबूत करता है, जिसका अपेक्षाकृत कम उपयोग किया गया है।
- o विकसित भू-राजनीति (जैसे, यूएस-चीन प्रतिद्वंद्विता) के बीच भारत की वैश्विक साझेदारी में विविधता लाता है।

चुनौतियाँ और विचार

- ब्रिक्स में चीन की भूमिका: चीन ब्रिक्स एजेंडे पर हावी होने का प्रयास कर सकता है; भारत को दृढ़तापूर्वक अपने रणनीतिक स्थान को सुरक्षित रखना चाहिए।
- कूटनीतिक बैंडविड्थ: एक साथ कई नए साझेदारों को जोड़ने के लिए मजबूत अनुवर्ती तंत्र की आवश्यकता होती है।
- भू-अर्थशास्त्र: कूटनीतिक संबंधों को व्यापार और निवेश लाभ में बदलना एक सतत चुनौती बनी हुई है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: वैश्विक दक्षिण के साथ भारत का जुड़ाव क्षेत्रीय नेतृत्व से वैश्विक राजनेता की ओर बदलाव को दर्शाता है।" प्रधानमंत्री मोदी की हाल की पांच देशों की यात्रा के आलोक में, इस कथन की आलोचनात्मक जांच करें। (250 Words)

Page : 06 : GS 2 : Social Justice

आईसीएमआर और एम्स के अध्ययनों के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि कोविड-19 टीकाकरण और अचानक होने वाली अस्पष्टीकृत मौतों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, खासकर युवा वयस्कों (18-45 वर्ष) में। अध्ययनों ने इसके बजाय आनुवंशिक, जीवनशैली, कोविड के बाद और पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों को संभावित योगदानकर्ता के रूप में उजागर किया।

'No link between COVID-19 vaccines and sudden deaths'

Sudden cardiac deaths can be from a wide range of factors, including genetics, lifestyle, pre-existing conditions, and post-COVID-19 complications, says Union Health Ministry

The Hindu Bureau
NEW DELHI

There is no direct link between COVID-19 vaccination and reports of sudden deaths in the country, the Union Health Ministry said on Wednesday. The Ministry added that this conclusion was reached following investigations conducted by multiple agencies.

The Ministry said that studies conducted by the Indian Council of Medical Research (ICMR) and the National Centre for Disease Control (NCDC) found no major changes in the patterns of causes of death when compared to previous years. In the majority of unexplained cases, genetic mutations were found to be a likely contributing factor.

"Sudden cardiac deaths can result from a wide range of factors, including genetics, lifestyle, pre-existing conditions, and post-COVID complications," the Ministry said in a statement.

The Ministry noted that both ICMR and NCDC have been working together to determine the causes behind sudden unexplained deaths, particularly among young adults aged between 18 and 45 years.

Fact check: COVID-19 vaccination does not increase the risk of unexplained sudden deaths in young adults, says study. VIJAY SONEJI

To investigate the phenomenon, two complementary studies were undertaken. The first, conducted by the ICMR's National Institute of Epidemiology (NIE), was a retrospective multicentric matched case-control study. Titled "Factors associated with unexplained sudden deaths among adults aged 18-45 years in India", it was conducted between May and August 2023 across 47 tertiary care hospitals in 19 States and Union Territories.

The study reviewed cases of individuals who appeared to be healthy but died suddenly between October 2021 and March 2023.

Its findings confirmed that COVID-19 vaccination does not increase the risk of unexplained sudden deaths in young adults.

The second study, titled "Establishing the cause in sudden unexplained deaths in young," is a prospective investigation currently under way at the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi. The study is being conducted in collaboration with the ICMR.

Preliminary findings from this study suggest that myocardial infarction (heart attack) continues to be the leading cause of sudden death in this demographic.

"Together, these two studies offer a more comprehensive understanding of sudden unexplained deaths in young adults in India. It has also been revealed that COVID-19 vaccination does not appear to increase the risk, whereas the role of underlying health issues, genetic predisposition and risky lifestyle choices does play a role in unexplained sudden deaths," the Ministry said.

Scientific experts have reiterated that claims linking COVID-19 vaccination to sudden deaths are "false and misleading" and not supported by scientific consensus. "Speculative claims without conclusive evidence risk undermining public confidence in vaccines, which have played a crucial role in saving millions of lives during the pandemic," the Ministry said. "Such unfounded reports and claims could strongly contribute to vaccine hesitancy in the country, thereby adversely impacting public health," it added.

मुद्दे की मुख्य बातें

सरकार की प्रतिक्रिया:

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वैक्सीन से संबंधित डर साक्ष्य पर आधारित नहीं है। अचानक होने वाली मौतों के कारणों की जांच करने के लिए पूर्वव्यापी और भावी दोनों तरह के अध्ययन किए गए।

अध्ययन विवरण:

1. ICMR-NIE अध्ययन:

- 19 राज्यों के 47 तृतीयक देखभाल अस्पतालों में पूर्वव्यापी, बहुकेंद्रित केस-कंट्रोल अध्ययन (मई-अगस्त 2023)।
- निष्कर्ष: टीकाकरण और अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई संबंध नहीं है।

2. एम्स-ICMR अध्ययन (चल रहा है):

- अचानक होने वाली मौतों के कारणों का पता लगाने पर केंद्रित भावी अध्ययन।
    - निष्कर्ष: मायोकार्डियल इंफार्क्शन (दिल का दौरा) इसका प्रमुख कारण है, न कि टीके।

पहचाने गए जोखिम कारक:

- आनुवंशिक उत्परिवर्तन
- कोविड-19 के बाद की जटिलताएँ
- पहले से मौजूद चिकित्सा स्थितियाँ
- अस्वास्थ्यकर जीवनशैली की आदतें (आहार, धूम्रपान, शारीरिक गतिविधि की कमी)

सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के लिए निहितार्थ

1. वैक्सीन पर भरोसा और हिचकिचाहट

- वैक्सीन को अचानक होने वाली मौतों से जोड़ने वाली भ्रामक कहानियाँ टीकाकरण कार्यक्रमों में जनता के भरोसे को कम कर सकती हैं।
- वैक्सीन हिचकिचाहट टीकाकरण अभियान और महामारी की तैयारियों में बाधा डाल सकती है।

2. साक्ष्य-आधारित संचार का महत्व

- विश्वसनीय संस्थानों (ICMR, AIIMS, NCDC) से पारदर्शी, वैज्ञानिक संचार की आवश्यकता को पुष्ट करता है।
- सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं का मुकाबला करने और घबराहट-आधारित नीति प्रतिक्रियाओं को रोकने में मदद करता है।

3. महामारी विज्ञान निगरानी को मजबूत करना

- देश भर में केस-कंट्रोल और संभावित अध्ययन शुरू करने का भारत का कदम वास्तविक समय की सार्वजनिक स्वास्थ्य जांच के लिए बढ़ती संस्थागत क्षमता को दर्शाता है।
- अन्य विकासशील देशों के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है।

4. संस्थाओं की भूमिका

- ICMR, AIIMS और NCDC जैसे शीर्ष स्वास्थ्य संस्थानों के महत्वपूर्ण कार्य पर प्रकाश डालता है:
  - o टीकाकरण के बाद निगरानी
  - o सार्वजनिक जोखिम संचार
  - o टीकाकरण और स्वास्थ्य रणनीतियों के लिए नीतिगत प्रतिक्रिया

चुनौतियाँ उजागर की गईं

- गलत सूचना और सार्वजनिक विश्वास की कमी: गलत सहसंबंध (जैसे, टीकों और मृत्यु के बीच) टीकाकरण से इनकार और सरकारी स्वास्थ्य अभियानों में अविश्वास का कारण बन सकते हैं।
- आनुवंशिक और जीवनशैली जांच की आवश्यकता: स्वस्थ दिखने वाले वयस्कों में बड़ी संख्या में मौतें निवारक स्वास्थ्य और प्रारंभिक निदान तंत्र में अंतर को दर्शाती हैं।
- मीडिया की जवाबदेही: असत्यापित दावों का प्रवर्धन सार्वजनिक धारणा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों के वर्षों को कमजोर कर सकता है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: वैज्ञानिक संचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में विश्वास महामारी से निपटने के लिए प्रभावी हैं। भारत में वैक्सीन से जुड़ी गलत सूचना और अचानक होने वाली मौतों के संदर्भ में, इस कथन की आलोचनात्मक जांच करें। (250 Words)

Page 06 : Prelims Pointer

इसरो ने घोषणा की है कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की मौजूदगी वाला एक्सिओम-4 (एक्स-04) मिशन भारत के स्वदेशी मानव अंतरिक्ष यान मिशन - गगनयान के लिए महत्वपूर्ण अनुभवात्मक डेटा प्रदान करेगा। यह मिशन भारतीय हस्तशिल्प को अंतरिक्ष में भेजकर भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करता है।

Axiom-4 trip to the ISS will provide valuable inputs for Gaganyaan mission: ISRO

The Hindu Bureau
BENGALURU

The Indian Space Research Organisation (ISRO) said the Axiom-4 (Ax-04) mission to the International Space Station will provide valuable inputs for India's upcoming Gaganyaan mission. Group Captain Shubhanshu Shukla is part of the Axiom mission.

"The Ax-04 mission will provide valuable inputs for ISRO's upcoming Gaganyaan mission. It offers hands-on experience about the nuances of international crew integration, medical and psychological preparation, real-time health telemetry, experiment execution, and crew-ground coordination," the ISRO said. It added that these insights will directly influence mission planning, safety validation, and

Shubhanshu Shukla is carrying a selection of the finest Indian handicrafts to ISS, says ISRO.

astronaut readiness for India's first indigenous human spaceflight mission.

"This is one small step in orbit, but a giant leap in India's pursuit of human spaceflight and scientific discovery," it added.

The ISRO said preparations are in progress for abort missions of the Gaganyaan mission and the first uncrewed test flight is targeted for the fourth quarter of 2025.

It added that the first crewed flight of the Gaganyaan mission is expected by the first quarter of 2027.

The ISRO said that as a tribute to India's rich cultural heritage, Mr. Shukla is carrying a selection of the finest of Indian handicrafts to the International Space Station. "These symbolic items, designed by students of the National Institute of Design, Ahmedabad, reflect the diversity, craftsmanship, and timeless beauty of India's traditional art forms, carefully curated to represent different regions and materials. These pieces serve as cultural ambassadors in space. Their journey aboard the ISS not only celebrates India's artistic legacy but also honours generations of artisans who continue to keep these traditions alive," it said.

यह क्यों महत्वपूर्ण है: गगनयान के लिए एक्सिओम-4 की रणनीतिक प्रासंगिकता

1. मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए क्षमता निर्माण

- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर किसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री द्वारा पहला प्रत्यक्ष चालक दल का अनुभव।

निम्नलिखित में व्यावहारिक पाठ:

- अंतर्राष्ट्रीय चालक दल सहयोग
- स्वास्थ्य निगरानी और मनोवैज्ञानिक तैयारी
- माइक्रोग्रैविटी प्रयोग निष्पादन
- ग्राउंड कंट्रोल के साथ संचार

2. गगनयान डिज़ाइन और निष्पादन के लिए फीडबैक लूप

मान्य करने में मदद करेगा:

- अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण मॉड्यूल
- सुरक्षा प्रणाली और आपातकालीन प्रोटोकॉल
- मिशन सिमुलेशन प्रक्रियाएँ

  o भारतीय सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण और वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संचालन के बीच की खाई को पाटता है।

अंतरिक्ष में सांस्कृतिक कूटनीति

- NID अहमदाबाद के छात्रों द्वारा तैयार भारतीय हस्तशिल्प को ISS में ले जाया जा रहा है:

  o भारत की कलात्मक विरासत, क्षेत्रीय विविधता और पारंपरिक शिल्प कौशल का प्रतिनिधित्व करता है।

  o वैश्विक वैज्ञानिक डोमेन में सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देता है।

  o "कक्षा में सांस्कृतिक राजदूत" के रूप में कार्य करता है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कूटनीति के लिए व्यापक निहितार्थ:

- वैश्विक मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों में भारत की स्थिति को बढ़ाता है।
- इसरो-नासा/एक्सिओम सहयोग और तकनीकी आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।
- उपग्रह प्रक्षेपणों से परे भारत को एक महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है।

विज्ञान और सार्वजनिक जुड़ाव के लिए:

- वास्तविक अंतरिक्ष यात्री भागीदारी के माध्यम से STEM में युवाओं की रुचि जगाता है।
- विज्ञान को संस्कृति से जोड़ता है, यह दर्शाता है कि परंपरा और नवाचार कैसे सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।

सांस्कृतिक संवर्धन के लिए:

- वैश्विक मंच पर हस्तशिल्प का प्रदर्शन करके अंतरिक्ष कूटनीति में भारत की सॉफ्ट पावर का विस्तार करता है।
- कारीगरों और भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को श्रद्धांजलि देता है।

आगे की चुनौतियाँ

- गगनयान की तकनीकी जटिलता - सुरक्षा प्रणाली, पुनः प्रवेश तंत्र और जीवन-सहायक तकनीक को परिपूर्ण किया जाना चाहिए।
- प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र - भारत में मजबूत अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।
- बजट और समयसीमा प्रबंधन – विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए देरी को न्यूनतम किया जाना चाहिए।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: एक्सिओम-4 जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशनों में भारत की भागीदारी मानव अंतरिक्ष उड़ान में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक मील का पत्थर है।" गगनयान मिशन के संदर्भ में चर्चा करें।

Page 07 : GS 3 : Science and Technology

एक अभूतपूर्व आनुवंशिक अध्ययन से पता चला है कि श्रीलंका के सिंहली लोग दक्षिण भारतीय द्रविड़ भाषी आबादी और श्रीलंका के आदिवासी (स्वदेशी) समुदायों के साथ घनिष्ठ आनुवंशिक संबंध साझा करते हैं। संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण पर आधारित यह शोध उत्तरी भारतीय वंश के बारे में पुरानी धारणाओं को चुनौती देता है और सिंहली जीन पूल के दक्षिण भारतीय मूल का समर्थन करता है, जो लगभग 3,000 साल पुराना है।

Sinhalese migrated from Southern India, mixed with Adivasis: study

The formation of the Sinhalese genetic pool is dated to about 3,000 years ago, falling within the range of dates displayed broadly by Indian and other Sri Lankan populations, and around the time of the proposed migration date of Sinhalese to their present homeland in the Sinhala chronicles

R. Prasad

Analyses of whole-genome sequence data of urban Sinhalese and two indigenous Adivasi clans in Sri Lanka, which live in geographically separated regions in the country, have shed light on the migratory history of these populations and their genetic relationship to each other and to many Indian populations.

The study, published recently in the journal *Current Biology*, found that Sinhalese and Adivasi are genetically closest to each other and to South Indians, but at a regional and fine-scale level, the two Adivasi clans are genetically distinct.

For the study, whole genomes of 35 urban Sinhalese individuals and 19 individuals from two indigenous Adivasi clans were sequenced. Of the 19 genomes of Adivasi clans that were sequenced, five were from among Interior Adivasi and 14 were from among Coastal Adivasi.

A genetic perspective

The sampling and data generation were possible due to the outreach efforts of Sri Lankan collaborator Ruwandi Ranasinghe, from the University of Colombo. In addition, the whole genome data of 35 Sri Lankan Tamils sampled in the U.K., which were already sequenced as part of the 1,000 Genomes Project, were included in the analyses.

Sinhalese chronicles and previous genetic studies had proposed that the Sinhalese people had migrated from northern or northwest India around 500 BCE, though their exact origins and migratory history are still debated. That the Sinhalese speak an Indo-European language, Sinhala, whose present-day distribution lies primarily in northern India, further supported the idea of their migration from northern India. But the current study contradicted the findings of the previous studies from a genetic perspective.

"The genetic ancestries and their proportions in the Adivasi and Sinhalese are most similar to Dravidian speaking populations, which live in Southern India today," Niraj Rai of the Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP), Lucknow, and one of the corresponding authors of the paper, told *The Hindu*.

"Even among South Indian populations, we find that the Sinhalese are genetically closest to those communities that have higher proportions of the so-called ASI or Ancestral South Indian ancestry," Maanasa Raghavan, assistant professor at the University of Chicago and a corresponding author of the study, said.

"In contrast to many North Indians, these populations generally have lower levels of a genetic ancestry related to ancient groups from the Eurasian Steppe, proposed to have carried Indo-European languages into South Asia and that are today spoken widely in northern regions of India."

Genes and linguistic affinities

But how does one reconcile the fact that the Sinhalese people speak a language that is classified as Indo-European, which today is spoken mostly in North India?

The authors explained that genes do not reflect linguistic affinities and that biological and cultural evolution can have different trajectories. They have speculated that this genetic-linguistic discordance may have been caused by the Sinhalese population having migrated from somewhere in North India geographically, but genetically speaking, the migration may have come from a group that resembles more South Indian Dravidian speakers today.

An alternative explanation is that a small group of Sinhalese people, perhaps representing the elite, might have migrated to Sri Lanka and transmitted the language but not the genes.

"If the Sinhalese were derived from a North Indian genetic cluster with higher Steppe-related ancestry, mixing had to have happened with ASI populations to dilute their genetic ancestries and pull them genetically closer to South Indian populations in our analyses. More anthropological studies are needed to fully understand these differing genetic and cultural affinities of the Sinhalese," Raghavan said.

Support from anthropological studies

The time of formation of the Sinhalese genetic pool was dated in the study to about 3,000 years ago, falling within the range of dates displayed broadly by Indian and other Sri Lankan populations and around the time of the proposed migration date of the Sinhalese in the chronicles (500 BCE).

"The date our analysis reveals is interesting. It implies that the Sinhalese ancestors migrated to Sri Lanka fairly close in time to the dynamic genetic mixing events that were occurring about 2,000-4,000 years ago in India that created the ANI-ASI genetic spectrum we see in today's populations," Rai explained. (ANI stands for 'ancestral north India' and ASI for 'ancestral south Indian'.)

Sinhalese chronicles also say that when the Sinhalese people migrated from India to Sri Lanka about 3,000 years ago, the Adivasi were already living in Sri Lanka. This is also supported by anthropological studies that propose that the Adivasi are descended from early hunter-gatherers in the region. The Adivasi are in fact traditionally hunter-gatherers and the Indigenous peoples of Sri Lanka.

"At a broad scale, Adivasi today look genetically very similar to the Sinhalese and Sri Lankan Tamil. This must mean that the Sinhalese, Sri Lankan Tamils, or other groups migrating from South India must have met the Adivasi, mixed with them heavily, and contributed to what is the present-day genetic structure of the Adivasi," Raghavan said.

> The genetic ancestries and their proportions in the Adivasi and Sinhalese are most similar to Dravidian speaking populations, which live in Southern India today

The Sinhalese and the Adivasi are close to each other and share broad-level genetic similarities. On a finer-scale demographic resolution, however, the study found that the two Adivasi clans are a bit different from the Sinhalese. The Adivasi have slightly higher levels of ancient hunter-gatherer ancestry than the Sinhalese and the Sri Lankan Tamils, and have maintained smaller population sizes over the course of their history, both of which support their traditional hunting and gathering lifestyle.

The Adivasi genomes also display signatures of endogamy, which appear as long stretches of DNA inherited from a common ancestor. The study further reported that a consequence of the low population size and endogamy is that the genetic diversity among the Adivasi is lower than that in the urban populations, which may have an impact on their health and disease status.

While both Adivasi clans have maintained lower population sizes compared to the Sinhalese and Sri Lankan Tamils, the authors found that the Interior Adivasi clan seemed to have undergone a stronger reduction in their population size compared to the Coastal Adivasi, leading to a greater loss of their genetic diversity.

"We find the two Adivasi clans – the Coastal Adivasi and the Interior Adivasi – also have some differences in their genetic ancestry arising due to distinct geographic separation between them," Rai said.

This, according to Raghavan, indicated that the Interior Adivasi clan must have undergone stronger pressures, perhaps societal or environmental, to keep the population size lower compared to their Coastal counterparts. Explaining how the two Adivasi clans are more similar to each other, but still have genetic differences at a fine scale, she said that this basically means at some point in time, due to geographic separation, the genetic and lifestyle attributes of the two clans started to drift apart.

Capturing the population history

In fact, the fragmented nature of the Adivasi clans also impacted the study sampling strategy. While 35 individuals representing the two large groups – Sinhalese and Sri Lankan Tamils – have been included in the analyses, the numbers for the two Adivasi populations were small: five from among the interior Adivasi and 14 from among the Coastal Adivasi.Though it would be ideal to keep matched sample sizes of different populations for genetic analyses, the reason for including only small numbers for the two Adivasi clans was because the Adivasi communities today are very fragmented.

"Historical, anthropological, as well as our genetic results all suggest that these communities live in small sizes and practice endogamy," Raghavan said. "Because of endogamy, a lot of these individuals tend to be quite related to one another. Having really high relatedness in a group impacts the genetic analyses because then everybody's going to look like each other. So that's why our sample sizes were lower for the two Adivasi clans."

Despite the number of individuals representing the two Adivasi clans being small, the researchers were able to recapture the entire population history of these two groups. The study was able to address the questions that the researchers set out to do despite the Adivasi sample sizes being small, according to Raghavan.

"Since every individual's genome is a mosaic of their ancestor's genomes, even a small number of individuals can represent their population's genetic histories. Moreover, we didn't find any genetic outliers within the Adivasi clans. So, all the sampled individuals fit into the model that we propose," Rai clarified.

"This is the first time that high-resolution genome data have been sequenced from multiple populations in Sri Lanka, including the Indigenous Adivasi and urban Sinhalese, to understand the deeply rooted ancestries and their population histories," Rai added.

Broadly, the study has important implications for how humans moved across South Asia and highlights the high degree of interconnectedness between India and Sri Lanka over millennia.

(prasad.ravindranath@thehindu.co.in)

Genes don't reflect linguistic affinities and biological and cultural evolution can have different trajectories. Representative image. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

A map of Sri Lanka showing the majority ethnicity by DS Division according to the country's 2012 Census. Yellow: Indian Tamils; purple: Sinhalese; green: Sri Lankan Moor; maroon: Sri Lankan Tamil; white: no majority. DEPARTMENT OF CENSUS & STATISTICS, SRI LANKA

A photograph of a Sinhalese family, c. 1880-1899. PUBLIC DOMAIN

A group of Adivasi men photographed in Sri Lanka c. 1870-1904. PUBLIC DOMAIN

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

1. दक्षिणी भारतीय आनुवंशिक समानता:

- सिंहली और श्रीलंकाई आदिवासी द्रविड़ भाषी दक्षिण भारतीय आबादी के साथ सबसे अधिक आनुवंशिक समानता दिखाते हैं।
- आनुवंशिक प्रोफ़ाइल एएसआई (पैतृक दक्षिण भारतीय) वंश से एएनआई (पैतृक उत्तर भारतीय) की तुलना में अधिक मेल खाती है।

2. प्रवास की समयरेखा:

- सिंहली आनुवंशिक पूल गठन: ~3,000 साल पहले।
- 500 ईसा पूर्व के आसपास श्रीलंका में सिंहली प्रवास को दर्ज करने वाले इतिहास से मेल खाता है।

3. सांस्कृतिक-भाषाई असंगति:

- एक इंडो-यूरोपीय भाषा (सिंहल) बोलने के बावजूद, सिंहली दक्षिण भारतीय प्रकार के जीन रखते हैं।
- परिकल्पना: भाषा को महत्वपूर्ण आनुवंशिक छाप के बिना एक छोटे से कुलीन समूह द्वारा पेश किया गया हो सकता है।

4. आदिवासी अंतर्दृष्टि:

- **दो आदिवासी कुलों (तटीय और आंतरिक) से पता चलता है:**
  - उच्च प्राचीन शिकारी-संग्राहक वंश
  - आनुवंशिक अंतर्विवाह और कम जनसंख्या विविधता
  - भौगोलिक रूप से अलग-अलग विकास, आनुवंशिक विचलन की व्याख्या

5. श्रीलंकाई तमिल और आदिवासी:

- आनुवंशिक समानताएँ भी साझा करते हैं, जो समान दक्षिण भारतीय वंश और ऐतिहासिक अंतर्संयोजन का समर्थन करते हैं।

अध्ययन के महत्वपूर्ण निहितार्थ

1. ऐतिहासिक मान्यताओं को फिर से लिखना

- पिछली मान्यता: सिंहली उत्तरी भारत से आए थे (भाषाई संबद्धता के आधार पर)।
- नए साक्ष्य: आनुवंशिक संरचना दक्षिणी भारत के साथ अधिक संरेखित होती है।
- इस बात पर प्रकाश डालता है कि भाषाई और आनुवंशिक विकास हमेशा एक समान नहीं होते हैं।

2. भारत-श्रीलंका सांस्कृतिक संबंध

- श्रीलंका में सहस्राब्दी पुराने दक्षिण भारतीय प्रवास के सिद्धांत को मजबूत करता है।
- पाक जलडमरूमध्य में गहरे सभ्यतागत संबंधों का समर्थन करता है।

3. वैज्ञानिक उन्नति

- सिंहली और आदिवासी आबादी की पहली उच्च-रिज़ॉल्यूशन जीनोम अनुक्रमण।
- प्रवासी इतिहास को फिर से लिखने में जीनोमिक्स की शक्ति को दर्शाता है।

4. स्वदेशी ज्ञान का संरक्षण

- आदिवासी कबीले अद्वितीय पैतृक आनुवंशिक हस्ताक्षरों को दर्शाते हैं, अंतर्जातीय विवाह के कारण विविधता कम होती है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: दक्षिण एशिया का जनसंख्या इतिहास प्रवास, सांस्कृतिक परिवर्तन और जैविक मिश्रण का एक जटिल अंतर्संबंध है। हाल के जीनोमिक अध्ययनों के प्रकाश में, श्रीलंका के संदर्भ में इस कथन की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। (250 Words)

Page : 09 : GS 3 : Indian Economy

नीतियों और योजनाओं में औपचारिक मान्यता के बावजूद, भारत के प्राथमिक श्रम सर्वेक्षण - आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) में गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक सांख्यिकीय रूप से अदृश्य बने हुए हैं। 2025 पीएलएफएस ने अभी तक कोई वर्गीकरण तंत्र शुरू नहीं किया है जो गिग कार्य की सटीक पहचान और ट्रैकिंग कर सके, इस प्रकार नीति कार्यान्वयन और सामाजिक सुरक्षा की प्रभावकारिता सीमित हो जाती है।

Are gig workers a part of India's labour data?

Though gig work is technically included under economic activity in the Periodic Labour Force Survey, without a specific classification, the survey fails to offer visibility into the unique nature of digital labour, characterised by multiple job roles, dependence on algorithms, lack of formal contract and absence of safety metrics

ECONOMIC NOTES

Durga Narayan

The 2025 Union Budget took several measures to formally 'recognise' gig and platform workers, and extended various social protection schemes to this growing workforce. Despite this recognition, the revised Periodic Labour Force Survey (PLFS), 2025 does not include substantive changes to account for the diverse forms of gig and platform work.

Gaps in labour classification

Gig workers were first incorporated into the legal framework through the Code on Social Security, 2020. Under Chapter I, Section 2(35), a gig worker is defined as "a person who participates in a work arrangement and earns from such activities outside of a traditional employer-employee relationship." Platform work, as defined in the Code, is "a work arrangement outside of a traditional employer-employee relationship in which organisations or individuals use an online platform to access other organisations or individuals to solve specific problems or to provide specific services or any such other activities which may be notified by the Central Government, in exchange for payment."

While this definition separates gig workers from both formal and informal categories, it doesn't clearly define who a gig worker is or the nature of gig work. According to NITI Aayog's 2022 report 'India's Booming Gig and Platform Economy,' the gig workforce is expected to reach 23.5 million by 2029-30. Despite such projections and efforts to define gig work, India's primary labour statistics source, the PLFS, continues to subsume gig work under vague categories such as 'self-employed', 'own-account workers', or 'casual labour'. This statistical invisibility has direct consequences.

Clause 141 of the Code on Social Security, 2020, "seeks to provide that the Central Government shall establish a Social Security Fund for social security and welfare of the unorganised workers, gig workers and platform workers." Similarly, the National Social Security Board, constituted under Section 6 of the Code on Social Security, 2020, is tasked with framing and overseeing welfare schemes for gig and platform workers. Such welfare boards and policymakers rely on the PLFS for 'evidence-based policy,' but the absence of a distinct category for gig and platform workers undermines its very intent. When classification itself is unclear in primary datasets, access to schemes becomes uneven and exclusionary.

On the periphery: Gig workers prepare to deliver orders in New Delhi, in 2024. REUTERS

How the PLFS falls short

In response to a Rajya Sabha query on whether the government had updated PLFS methodology to capture the rise of gig work, the Ministry of Statistics and Programme Implementation stated, "No updation in the PLFS Schedule has been undertaken with the objective of specifically identifying persons engaged in the gig economy. However, all market activities i.e. activities performed for pay or profit which result in production of goods and services for exchange are included under the domain of economic activity considered in PLFS. The activity situation of a person who is found to be working or being engaged in economic activity during a specified reference period is associated with employment in PLFS. Hence, even the persons engaged in 'gig economy' for pay & profit are covered in PLFS."

Though gig work is technically included under economic activity, without a specific category or classification, the survey fails to offer visibility into the unique nature of digital labour, characterised by multiple job roles, dependence on algorithms, lack of formal contract and absence of safety metrics. In the survey, while the question on the type of job contract provides an option for 'no written job contract', it doesn't capture the hybrid nature of work.

Unlike traditional self-employment, gig work is shaped by platform algorithms, performed across multiple apps and are mostly task-based rather than time-bound. Workers have no stable contracts, and often rely on digital reach. Many lack access to benefits or protections available to formal workers, and don't fully own their work processes, making the "self-employed" label misleading. Employment uncertainties, income volatility and algorithm governance remain invisible within PLFS classification. A food delivery person working across platforms like Swiggy, Zomato, for instance, will be flattened into a category that does not reflect entirely on their employment conditions or social security needs.

Recognition without representation

Recent policy efforts like the e-Shram registration, the issuance of digital ID cards, and health coverage under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana indicate the state's recognition of the gig and platform workforce. But unless statistical systems like the PLFS evolve, the data meant to support and monitor these interventions cannot be considered inclusive.

The 2025 PLFS revision introduced some important updates: a larger sample size, monthly estimates, and better rural representation. However, it still does not address the issues of how gig work is defined and understood. For inclusive policy making, India must update PLFS classification codes or introduce survey modules that distinctly capture gig work.

Durga Narayan is a policy researcher affiliated with the Indian Institute for Human Settlements (IIHS) and the Observer Research Foundation (ORF), Mumbai.

THE GIST

- Gig workers were first incorporated into the legal framework through the Code on Social Security, 2020.
- According to NITI Aayog's 2022 report 'India's Booming Gig and Platform Economy,' the gig workforce is expected to reach 23.5 million by 2029-30.
- Unlike traditional self-employment, gig work is shaped by platform algorithms, performed across multiple apps and are mostly task-based rather than time-bound. Workers have no stable contracts, and often rely on digital reach.

मुख्य अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

- गिग वर्कर (सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020): कोई व्यक्ति जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से बाहर काम करके कमाता है।
- प्लेटफ़ॉर्म वर्कर: सेवाएँ देने या कार्यों को हल करने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से काम करता है - जैसे, स्विगी, उबर, अर्बन कंपनी।

- पीएलएफ़एस (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण): भारत का प्राथमिक श्रम डेटा स्रोत, जिसका उपयोग रोज़गार प्रवृत्ति विश्लेषण और नीति निर्माण के लिए किया जाता है।

प्रमुख मुद्दे उजागर किए गए

1. अपर्याप्त श्रम वर्गीकरण

- गिग वर्कर को "स्व-नियोजित", "स्व-खाता वाले कर्मचारी" या "आकस्मिक श्रमिक" जैसी अस्पष्ट श्रेणियों में रखा जाता है।
- गिग वर्क की अनूठी स्थितियाँ - जैसे कई नौकरियाँ, कार्य-आधारित कार्य, एल्गोरिदम प्रबंधन, अनुबंध/सुरक्षा की कमी - को शामिल नहीं किया जाता है।

2. नीति-डेटा डिस्कनेक्ट

- कानून और योजनाएँ (जैसे सामाजिक सुरक्षा कोड 2020, ई-श्रम पोर्टल, आयुष्मान भारत) का उद्देश्य गिग वर्कर्स को शामिल करना है।
- लेकिन पीएलएफएस में अलग-अलग कोड नहीं हैं, जिससे गिग वर्कर्स डेटा नेट से बाहर हो जाते हैं, जिससे कल्याणकारी योजनाओं में शामिल होना असंगत हो जाता है।

3. पीएलएफएस में संरचनात्मक ब्लाइंड स्पॉट

- पीएलएफएस सभी भुगतान गतिविधियों को "आर्थिक गतिविधि" मानता है, लेकिन ऐसा नहीं करता है:

  o प्लेटफ़ॉर्म कार्य के बारे में पूछें।

  o कई ऐप-आधारित भूमिकाएँ कैप्चर करें।

  o एल्गोरिदम नियंत्रण या नियोक्ता जवाबदेही की अनुपस्थिति पर विचार करें।

4. प्रतिनिधित्व के बिना मान्यता

- नीतिगत ध्यान के बावजूद, गिग वर्कर्स डेटासेट में दिखाई नहीं देते हैं, जिससे उनके अधिकारों और सुरक्षा की निगरानी करना मुश्किल हो जाता है।

आगे का रास्ता / सिफारिशें

1. पीएलएफएस सर्वेक्षण डिज़ाइन को अपडेट करें

  o गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के लिए विशिष्ट वर्गीकरण कोड पेश करें।

  o मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म आय, एल्गोरिथम नियंत्रण, अनुबंध की स्थिति और लाभ कवरेज को कैप्चर करें।

2. गिग वर्क मॉड्यूल विकसित करें

- o प्लेटफ़ॉर्म-आधारित कार्य की विविध प्रकृति को कैप्चर करने के लिए PLFS या टाइम यूज़ सर्वे में स्टैंडअलोन या एम्बेडेड मॉड्यूल।

3. डेटा-नीति तालमेल

- o वास्तविक समय में गिग अर्थव्यवस्था के आकार, भेद्यता और रुझानों को मैप करने के लिए ई-श्रम डेटा + PLFS अपग्रेड का उपयोग करें।

4. अंतर-मंत्रालयी समन्वय

- o श्रम मंत्रालय, MoSPI, नीति आयोग और राज्य श्रम बोर्डों को एकीकृत डेटा ढांचे पर समन्वय करना चाहिए।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: प्रतिनिधित्व के बिना मान्यता सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य को कमजोर करती है।" भारत में गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के संदर्भ में इस कथन की जाँच करें। (250 words)

Page : 08 Editorial Analysis

Rephasing global development finance

India's development cooperation with the Global South has been showing a rising trend for the last several years. India has made consistent efforts to expand the facets of these engagements and has also almost doubled the flow of quantum – from around $3 billion in 2010-11 to around $7 billion in 2023-24. While capacity building programmes and the initiatives for technology transfer and duty-free access to India markets have been important modalities of this engagement, the main instrument has been the extension of lines of credit (LoC) under the Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS).

If budgetary provisions for 2025-26 are any indication, the red flag from the Ministry of Finance on credit lines, as a modality of engagement, is absolutely clear. At the G-20, India expressed serious concerns over rising sovereign debt levels across the Global South. During the third Voice of Global South Summit (VoGS) in 2024, Prime Minister Narendra Modi articulated the concept of a Global Development Compact (GDC), thereby implying a harmonious balance between all the modalities of engagement with the Global South. It is worth noting that there are five modalities of engagement, *viz.*, capacity building, technology transfer, market access, grants and concessional finance. This balanced approach on modalities may be supplemented by India by having wider and deeper partnerships with countries that can work across third countries.

In this backdrop, under the modalities of engagement, India has to refocus on LoCs as an instrument of engagement. India was largely borrowing from global capital markets and providing the resources to the partner countries at a concessional rate of interest. The difference in the rates of interest was being absorbed by the Government of India. With a rising global liquidity crisis, such schemes have lost their relevance as capital market predictability and the repaying capabilities of partner countries have become severely constrained. India should take full advantage of this new reality.

Shrinking ODA and debt crisis

The traditional official development assistance (ODA) providers are going through their own budgetary crisis while the partners of the Global South have challenges in coping with the debt crisis. With rising geopolitical complexities, the flow of global development finance in any case is witnessing a profound decline. The collapse of USAID and the decline of the Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) have highlighted the emerging crisis in development finance. The availability and leveraging of resources have been hampered further by the declining trend in ODA, which is likely to be close to $97 billion. This proposed slashing of foreign aid is a near 45% reduction from the levels of ODA in 2023, which stood at around $214 billion. At the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), its Development Assistance Committee (DAC) has been an elite club for ODA providers, dictating the terms and conditions for the economic and political programmes for the South.

Sachin Chaturvedi

is Vice-Chancellor, Nalanda University, Rajgir, Bihar, and Director-General at the Research and Information System for Developing Countries (RIS), a New Delhi-based think-tank

With geopolitical complexities affecting global development finance, a solution lies in evolving a mechanism of pooling resources with like-minded countries

Shrinkage in the resource flow is likely to affect several development programmes, across least developed economies, particularly at a time when several of them are passing through an unprecedented debt crisis. Over the last 20 years, a series of overlapping crises and major geopolitical and economic transformations have reshaped the global financial environment, leaving many developing countries struggling to access funding. This has posed a risk to development progress at risk and jeopardised achievements.

The investment needed to achieve the Sustainable Development Goals (SDG) by 2030 has also surged from $2.5 trillion in 2015 to over $4 trillion in 2024. Without a major increase in financing, progress toward the SDGs (already derailed by the COVID-19 pandemic and other global shocks) will remain elusive. Simultaneously, borrowing has become costlier and less predictable.

Rationale for triangular cooperation

A ray of hope lies in the possibility of evolving a new mechanism of pooling resources with like-minded countries. The flows from the 19 non-DAC countries that report to the OECD rose from $1.1 billion in 2000 to $17.7 billion in 2022. Some of these countries such as Indonesia and Brazil have evolved a rich global experience with Japan and Germany of working in third countries. Japan and Indonesia have worked together in several Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) economies to implement development projects. Similarly, Germany and Brazil have worked together in Mozambique in multiple development areas. Triangular Cooperation (TrC) has emerged as a powerful mechanism to bridge the divide between the Global North and the Global South.

The beauty of the TrC is that it brings together a traditional donor from the Global North, a pivotal country from the Global South, and a partner country (often from the Global South), creating inclusive platforms for shared learning, mutual respect and the co-creation of solutions tailored to local needs. Comprehensive TrC data is still being compiled at the global stage. However, the efficacy and the success of the model has been well established. Some preliminary data collection suggests TrC to be between $670 million to $1.1 billion.

Partnerships with results

The TrC has shown that addressing physical infrastructure can advance social progress. For instance, improving regional energy grids expands digital connectivity and provides access to opportunities in education and health. In this context, in 2022, Germany and India signed a Joint Declaration of Intent on the implementation of TrC projects in third countries (during the sixth India-Germany Inter-Governmental Consultations), with a focus on Africa, Asia, and Latin America. Since then, TrC projects are being implemented in several countries which include Cameroon, Ghana and Malawi in Africa, and in Peru in Latin America.

These offer clear examples as to how to rephase global development finance in a manner that ensures assured and efficacious outcomes in a cost-effective manner. Engagement in TrC was further emphasised during India's G-20 presidency, with expanded collaborations involving countries such as Germany, the United States, the United Kingdom, the European Union, and France. These partnerships span a variety of sectors and modalities, from grant-based projects to investment-driven initiatives such as the Global Innovation Partnership (GIP) with the U.K. These efforts illustrate how leveraging technical, financial, and human resources can deliver results in third countries.

The views expressed are personal

Paper 02 अंतरराष्ट्रीय संबंध

UPSC Mains Practice Question: भारत का विकास साझेदारी मॉडल पारंपरिक उत्तर-प्रधान विकास सहायता के विकल्प के रूप में उभर रहा है।" वैश्विक दक्षिण के साथ भारत के जुड़ाव और त्रिकोणीय सहयोग की अवधारणा के प्रकाश में चर्चा करें। (250 words)

संदर्भ:

- बदलती वैश्विक भू-राजनीति और आर्थिक अस्थिरता की पृष्ठभूमि में, ग्लोबल साउथ के साथ भारत का विकसित होता विकास सहयोग अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त में रणनीतिक पुनर्संयोजन को दर्शाता है। आधिकारिक विकास सहायता (ODA) अनुबंध के पारंपरिक स्रोतों के रूप में, एक जिम्मेदार विकास भागीदार के रूप में भारत की भूमिका रियायती वित्त, क्षमता निर्माण और त्रिकोणीय सहयोग (TrC) जैसे वैकल्पिक तंत्रों के माध्यम से विस्तारित हो रही है। वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (2024) में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट की अभिव्यक्ति समावेशी, सहयोगी और संतुलित विकास साझेदारी के लिए एक दृष्टिकोण को दर्शाती है।

भारत का विकास सहयोग: तौर-तरीकों का विस्तार

- ग्लोबल साउथ के लिए भारत का विकास वित्त काफी बढ़ गया है - 2010-11 में $3 बिलियन से 2023-24 में लगभग $7 बिलियन तक।
- **प्रमुख साधनों में शामिल हैं:**
  o IDEAS योजना के तहत ऋण की लाइनें (LoCs)।
  o भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
  o अल्प विकसित देशों (एलडीसी) के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और शुल्क मुक्त बाजार पहुंच।
- हालांकि, बढ़ते वैश्विक ऋण संकट के कारण एलओसी पर अत्यधिक निर्भरता के खिलाफ वित्त मंत्रालय की चेतावनी जुड़ाव तंत्र में विविधता लाने की आवश्यकता को इंगित करती है।

वैश्विक संदर्भ: ओडीए में गिरावट और बढ़ता ऋण संकट

- वैश्विक ओडीए में तेज गिरावट देखी गई है, जिसमें लगभग 45% की कटौती प्रस्तावित है, जो 2023 में $214 बिलियन से $97 बिलियन हो गई है।
- यूएसएआईडी और एफसीडीओ जैसी पारंपरिक सहायता एजेंसियां संस्थागत कमज़ोरी का सामना कर रही हैं।
- इसके साथ ही, विकासशील देश ऋण के जाल में फंस गए हैं, उधार लेना महंगा हो गया है और कोविड-19 सहित वैश्विक संकटों के कारण वित्तीय पूर्वानुमान में गिरावट आ रही है।
- ये घटनाक्रम अल्प विकसित देशों की सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं - जहां निवेश अंतर $2.5 ट्रिलियन (2015) से बढ़कर $4 ट्रिलियन (2024) से अधिक हो गया है।

त्रिकोणीय सहयोग: नया प्रतिमान

- **त्रिकोणीय सहयोग (TrC) में शामिल हैं:**
  o वैश्विक उत्तर से एक दाता (जैसे, जापान, जर्मनी),
  o वैश्विक दक्षिण से एक महत्वपूर्ण देश (जैसे, भारत, ब्राजील),
  o एक भागीदार देश (जैसे, घाना, मोजाम्बिक, पेरू)।

- **TrC बढ़ावा देता है:**
  o साझा शिक्षा,
  o स्थानीय समाधान,
  o लागत प्रभावी वितरण,
  o उत्तर और दक्षिण के बीच आपसी सम्मान।

उदाहरण:

- अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में TrC परियोजनाओं के लिए भारत-जर्मनी संयुक्त घोषणा (2022)।
- कैमरून, घाना, मलावी और पेरू में परियोजनाएँ।
- यू.के. के साथ वैश्विक नवाचार भागीदारी (GIP) जैसी साझेदारियाँ स्केलेबल नवाचारों का समर्थन करती हैं।

भारत के लिए रणनीतिक महत्व

- वॉयस ऑफ़ ग्लोबल साउथ समिट, ब्रिक्स और जी-20 जैसे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से वैश्विक दक्षिण में नेतृत्व की भूमिका।
- विकास वित्तपोषण के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण, ऋण लाइनों से आगे बढ़कर:
  o अनुदान, तकनीकी सहायता और बाजार पहुंच।
  o तीसरे पक्ष के देशों के साथ सहयोगात्मक विकास।
- विकास के पारदर्शी और मांग-संचालित मॉडल के माध्यम से चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) को संतुलित करने की क्षमता।

निष्कर्ष

- वैश्विक विकास वित्त को फिर से परिभाषित करने के लिए ऋण-भारी, दाता-प्राप्तकर्ता संबंधों से हटकर अधिक न्यायसंगत और बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता है। भारत, त्रिकोणीय सहयोग और एक व्यापक विकास समझौते को अपनाकर, दक्षिण-दक्षिण सहयोग को अधिक लचीले, समावेशी और टिकाऊ तरीके से नया रूप दे रहा है। कम होते ODA और बढ़ती ऋण भेद्यता के युग में, भारत का मॉडल विकासात्मक कूटनीति के लिए एक खाका पेश करता है जो व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों है।